दैनिक जागरण
आसान कार्य भी आरंभ में कठिन प्रतीत होता है

ईवीएम पर बेतुकी बातें

खुद 99 सीटों के साथ सहयोगी दलों संग 232 सीटें जीतने वाली कांग्रेस जिस तरह ईवीएम पर हमलावर है, वह केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बल्कि शरारतपूर्ण भी है। ईवीएम के खिलाफ नए सिरे से जो अभियान छेड़ा गया है, उसका उद्देश्य केवल इस मशीन को अविश्वसनीय करार देना ही नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की साख को गिराना भी है। यह सब जानबूझकर किया जा रहा है, ताकि चुनाव आयोग के साथ-साथ मोदी सरकार को भी बदनाम किया जा सके। यदि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव होती तो विपक्षी दल भाजपा को 240 सीटों पर सीमित करने में सफल नहीं हुए होते। ईवीएम के खिलाफ ताजा अभियान अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क की इस टिप्पणी से शुरू हुआ कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है। हालांकि उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी ईवीएम के संदर्भ में थी, लेकिन उसे भारत की ईवीएम के संदर्भ में मान लिया गया। वह एक बड़े कारोबारी और तकनीक के जानकार हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह दुनिया की हर मशीन के ज्ञाता हैं। उनका यह भी दावा है कि ऐसी कोई इलेक्ट्रानिक मशीन नहीं, जिसे हैक न किया जा सकता हो। क्या इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर को हैक किया जा सकता है? क्या उनकी टेस्ला कार भी हैकिंग का शिकार हो सकती है? कोई कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो, उसे जिस चीज की समझ न हो, उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

ईवीएम के खिलाफ दिए जा रहे तर्क इसलिए निराधार और हास्यास्पद हैं, क्योंकि यदि उसे हैक किया जाना संभव होता तो कम से कम आइटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर महज 16 हजार वोटों से नहीं हारते और न ही भाजपा अयोध्या, अमेठी जैसी सीटें अपने हाथ से जाने देती। ईवीएम को बदनाम करने के लिए एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि उसे मोबाइल फोन के जरिये ओटीपी हासिल करके हैक किया जा सकता है। यह मूर्खता की पराकाष्ठा है, क्योंकि ईवीएम के संचालन में ओटीपी का कोई काम ही नहीं। चूंकि ईवीएम इंटरनेट आधारित नहीं है, इसलिए भी उसे हैक करने का सवाल नहीं उठता, लेकिन यह उन्हें नहीं समझ आएगा, जो अंधविरोध से ग्रस्त हैं। सबसे शर्मनाक यह है कि ईवीएम के खिलाफ अभियान में वह कांग्रेस सबसे आगे है, जिसके शासनकाल में ही इस मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ और जिसने ईवीएम के जरिये ही कई चुनाव भी जीते। ईवीएम के खिलाफ बेतुकी बातें इस आधार पर भी की जा रही हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट वाली शिवसेना का एक प्रत्याशी बहुत कम वोटों से चुनाव जीत गया। इस प्रत्याशी की जीत के बहाने ईवीएम को बदनाम करने वालों को यह पता होना चाहिए कि लोकसभा की 21 सीटें ऐसी रहीं, जहां हार-जीत का अंतर दस हजार या उससे कम रहा। इन सीटों में से अधिकांश पर विपक्षी दलों के उम्मीदवार जीते।

मानसून का इंतजार

झारखंड में अभी भी कृषि के लिए मानसून का इंतजार करने की परंपरा है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी संसाधनों को बढ़ाने के नियमित प्रयासों के बीच मानसून पर हमारा आश्रित होना कई मायनों में कृषि से संबंधित तैयारियों पर सवाल उठाता है। कई बार मौसम की बेरुखी के कारण खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता है और इससे वर्षा आधारित खेती को नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन इन तमाम बातों के बीच सवाल उठ रहा है कि अभी तक प्रदेश में खेतों तक पानी पहुंचाने की संरचनाएं तैयार क्यों नहीं हो सकी हैं। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले 50 से भी अधिक वर्षों में सरकारों ने लगातार इस पर फोकस किया है। इसपर अरबों रुपये खर्च हुए हैं। संयुक्त बिहार के समय से ही झारखंड में खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हो रहा है। कोयलकारो नदी परियोजना से लेकर कई चेक डैमों के निर्माण के पीछे की मंशा कहीं न कहीं यही रही है, परंतु शासन-प्रशासन इसमें अबतक असफल रहा है। इसी बीच पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दिशा में काम किया गया, जिसका लाभ भी किसानों को मिलना शुरू हो गया। इन क्षेत्रों में किसान अब खेती की शुरुआत के लिए मानसून पर निर्भर नहीं हैं। बिहार के भी कई क्षेत्रों में हालात सुधरे हैं, लेकिन झारखंड में व्यवस्था अभी भी मानसून पर निर्भर है। हालांकि झारखंड में भी दस लाख कूप, सिंचाई के लिए तालाब निर्माण और चेक डैम की परियोजनाओं पर काम किया गया है, परंतु योजनाओं में खामियों के कारण खेतों तक पानी पहुंचाने में सरकारों तंत्र फेल रहा है। इस पर मंथन करने की आवश्यकता है।

> संयुक्त बिहार के समय से ही झारखंड में खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हो रहा है, परंतु शासन-प्रशासन को इसमें सफलता नहीं मिली है

भारत भी बदले अपनी तिब्बत नीति

विजय क्रांति

तिब्बत संबंधी नया अमेरिकी कानून भारत और अन्य एशियाई देशों को चीन की दादागीरी से राहत दिलाने वाला है

अमेरिकी संसद द्वारा पारित तिब्बत और चीन से जुड़ा नया विधेयक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तिब्बत के मुद्दे को एक नई एवं सार्थक दिशा दे सकता है। 'तिब्बत-चीन विवाद को सुलझाने के लिए प्रोत्साहन संबंधी कानून (2024)' पर अब केवल अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने शेष हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस पर पूरी तरह अमल करना भावी अमेरिकी प्रशासन के लिए कानूनी बाध्यता बन जाएगा। यह कानून भले ही तिब्बत के निर्वासित शासक दलाई लामा और चीन सरकार को बातचीत के जरिये परस्पर विवाद सुलझाने में सहयोग करने वाले एक दोस्ताना कदम जैसा लगता हो, लेकिन इसकी भाषा से समझ आता है कि यह तिब्बत को 73 साल से चले आ रहे चीनी उपनिवेशवादी कब्जे से मुक्ति दिलाने के अभियान की घोषणा है। अमेरिका की इस नई पहल में भारत जैसे उन एशियाई देशों के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खुलने के आसार बनते दिख रहे हैं, जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वभौमिक हितों पर तिब्बत पर चीनी अवैध कब्जे के बाद खतरे बढ़े हैं।

अमेरिका की राजनीति में भले ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोफाड़ हों, मगर उक्त कानून पर दोनों दलों में सर्वसम्मति का भाव है और इसीलिए दोनों दलों के सांसद दलाई लामा से मिलने आ रहे हैं। इस कानून में तिब्बत को लेकर बेहद आक्रामक नीति अपनाने वाले राष्ट्रपति शी चिनफिंग के रवैये को चुनौती दी गई है। तिब्बत को चीन का 'अविभाज्य अंग' बताने, उससे जुड़े हर सवाल को चीन का 'आंतरिक' विषय कहने, तिब्बत की चर्चा मात्र पर आंखें तरेरने वाले एवं तिब्बत और अपनी 'बन-चाइना' पालिसी को लेकर अति आग्रही चिनफिंग की इससे जुड़ी नीतियों को नए कानून में अमान्य ठहराया गया है। इसमें चीन के हर उस दावे को झूठा घोषित किया गया है, जिन्हें पिछले 40 साल से चीन सरकार दलाई लामा के साथ वार्ता की मूलभूत शर्तों के रूप में पेश करती आई है। इसमें स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि तिब्बत एक कब्जाया हुआ देश है और वह इतिहास में कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा। चीन सरकार तिब्बत की निर्वासित सरकार के साथ बातचीत में तिब्बत की परिभाषा को मात्र 'तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र' (टार) तक सीमित मानती है, जबकि अमेरिकी कानून में 'तिब्बत' के दायरे में उसके खम एवं आम्दो प्रांतों के उन हिस्सों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें तिब्बत को कब्जाने के बाद उन्हें तिब्बत से काटकर युन्नान, सिचुआन, चिंघाई और गांसु जैसी सीमावर्ती चीनी प्रांतों में मिला दिया गया।

धर्मशाला में एक प्रार्थना सभा में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ●प्टि

नए कानून में धर्मशाला-बीजिंग की प्रस्तावित शांति वार्ताओं में तिब्बत की ओर से न केवल दलाई लामा और उनके प्रतिनिधियों को भाग लेने का अधिकारी माना गया है, बल्कि अब धर्मशाला में तिब्बती जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करके केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को 'तिब्बती सरकार' जैसे परोक्ष मान्यता भी दी गई है। दलाई लामा के अगले अवतार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का क्षेत्राधिकार घोषित करने पर तुले हुए चिनफिंग के जले पर नमक छिड़कते हुए उक्त कानून में स्पष्ट कहा गया है कि दलाई लामा या अन्य अवतारी लामाओं की खोज करने और उनकी नियुक्ति तथा शिक्षा-दीक्षा का एकमात्र अधिकार दलाई लामा और तिब्बती समुदाय का है। यदि इस मामले में चीन का कोई हस्तक्षेप पाया गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति और संबंधित अमेरिकी एजेंसियों की यह कानूनी जिम्मदारी होगी कि वे ऐसे सभी चीनी अधिकारियों पर जरूरी प्रतिबंध लगाएं। यह कानून अमेरिकी सरकार को तिब्बत के मामले में चीन के प्रत्येक दुष्प्रचार का जवाब देने और तिब्बत के समर्थन में वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संगठन बनाने का भी निर्देश देता है। तिब्बत को लेकर अमेरिकी सरकार एकाएक नहीं जागी। तिब्बत के समर्थन में अमेरिकी संसद दर्जनों बार कई कानून और प्रशासनिक आदेश पारित कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में तिब्बत के समर्थन में 1959, 1961 और 1965 के दौरान प्रस्ताव पारित कराने में अमेरिका ने शुरुआती प्रयास किए थे, लेकिन फिर चीन के साथ गलबहियां बढ़ाने के चलते तिब्बत का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया।

नए अमेरिकी कानून के कुछ प्रविधान भारत, नेपाल, भूटान और अन्य एशियाई देशों को चीन की दादागीरी से राहत दिलाने की राह दिखाने वाले हैं। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा है दलाई लामा के अगले अवतार पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार की चुनौती। इन तीनों देशों के समक्ष एक खतरा यह है कि अगर चीन सरकार अगले दलाई लामा और अन्य अवतारी लामाओं पर अपने नियंत्रण में सफल हो गई तो तिब्बती बौद्ध प्रभाव वाले पूरे हिमालयी क्षेत्र में चीनी दखल बढ़ जाएगा। इससे वहां चीन के लिए उथल पुथल बढ़ाने का रास्ता खुल जाएगा। तिब्बत-चीन विवाद में धर्मशाला के निर्वासित तिब्बती प्रशासन को अमेरिकी मान्यता से इन देशों को तसल्ली मिल जाएगी कि वर्तमान दलाई लामा के बाद चीन को तिब्बत में पूरी मनमानी करने और इन देशों के बौद्ध क्षेत्रों पर आक्रामकता बढ़ाने की छूट नहीं मिल पाएगी। तिब्बत को लेकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक लामबंदी की पहल से भी इन एशियाई देशों और विशेष रूप से भारत को एक ऐसा शक्तिशाली मंच उपलब्ध होगा, जहां से वह चीनी दबंगई को चुनौती दे पाएगा। भारत को भी अब तिब्बत पर अपनी नीति बदलनी होगी। चीनी आक्रामकता के शिकार भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को तिब्बत के सवाल को धार देनी होगी।

भारत के लिए तो नया अमेरिकी कानून ऐसा अवसर सिद्ध हो सकता है, जिसकी कमी उसे पिछले 70 वर्षों से खटकती आ रही थी। आज भारत को भलीभांति समझ आ चुका है कि वह हिमालयी क्षेत्र में चीनी दादागीरी का केवल इसीलिए शिकार हो रहा है, क्योंकि तिब्बत पर कब्जा जमाने के बाद चीनी सेनाएं भारत की सीमा तक आ पहुंची हैं। चीन अभी तिब्बत को अपनी छावनी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में यदि अमेरिका की पहल पर तिब्बत को चीन से मुक्ति मिल जाती है तो न केवल भारत, बल्कि नेपाल और भूटान भी चीन की दादागीरी से मुक्त हो जाएंगे।

(लेखक सेंटर फार हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार है)

response@jagran.com

सरकार के सामने परीक्षा की घड़ी

प्रेमपाल शर्मा

मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा-नीट में गड़बड़ी को मोदी सरकार को खतरे की घंटी के रूप में लेना चाहिए

आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यह स्वीकार करना पड़ा कि मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट-यूजी में कुछ गड़बड़ी हुई है। फिलहाल गड़बड़ी की व्यापकता का पता चलना शेष है, लेकिन नीट में अनियमितता का मामला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के लिए बहुत ही शर्म की बात है। वर्ष 2017 में इस एजेंसी का गठन इसीलिए हुआ था कि देश भर में मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाओं को इस तरह व्यवस्थागत किया जाए कि उनमें गड़बड़ी की आशंका न रहे और लाखों-करोड़ों युवा अपनी मेधा के बूते आगे बढ़ें। हमारे देश में जिस तरह अनैतिकता फैल चुकी है, उसे देखते हुए साफ-सुथरी प्रवेश या फिर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन एक बड़ी चुनौती बन गया है। देश के ज्यादातर राज्यों में स्कूली स्तर से लेकर विश्वविद्यालय के शोध पत्रों तक में नकल के मामले खुलेआम सामने आते हैं।

मेडिकल कालेजों में नामांकन के लिए देश के 20 लाख से अधिक युवा रात-दिन मेहनत करके तैयारी करते हैं। कई बार पढ़ाई के तनाव में वे डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं और कुछ आत्महत्य तक कर लेते हैं। इस तरह की खबरें आए दिन हमें पढ़ने को मिलती हैं। इस दौरान उनके अभिभावक भी कई समस्याओं से गुजरते हैं, विशेषकर गरीब अभिभावक। अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए वे एक यकीन के साथ उनके समर्थन में खड़े रहते हैं। ऐसे में जब परिणाम लोक होने या फिर परिणाम में धांधली की कोई खबर आती है तो उन्हें कितनी गहरी निराशा और पीड़ा होती होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इस बार नीट-यूजी में कहीं केंद्र बदले गए, कहीं समय का ध्यान नहीं रखा गया और अंत में पेपर लीक होने की भी बात सामने आई। इसी के साथ ग्रेस मार्क्स देने का मामला भी सामने आया। यह किसी के लिए समझना कठिन था कि ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए? जब एनटीए ग्रेस मार्क्स देने के अपने तर्कों का बचाव नहीं कर सका तो फिर उन्हें रद कर दिया गया।

देश में वर्षों से प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। इनमें शामिल लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद क्या होता है? क्या उनको ऐसी सजा मिलती है, जो एक नजीर बन सके? सिर्फ परीक्षा कराने में शामिल एजेंसियों का लाइसेंस रद करना या फिर सरकारी कर्मचारियों को निलंबित करना ही पर्याप्त नहीं है। वे तो इस धंधे में संलिप्त होकर पहले ही करोड़ों रुपये कमा चुके होते हैं और छोटे-मोटे दंड के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहते होंगे। उनको गिरफ्तार करके उन्हें जेल में बंद कर उनके साथ अपराधियों की तरह पेश आना चाहिए, भले ही हमारे लिबरल और उनके पोषक-प्रोत्साहक कुछ भी कहते रहें। इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि देश में कुछ गिरोह दशकों से इसी काम में लगे हुए हैं। वे कभी पुलिस, कभी शिक्षक, क्लर्क आदि की भर्ती के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के लिए सक्रिय होते हैं, तो कभी अन्य संस्थाओं में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में। हर परीक्षा उनके लिए भ्रष्टाचार और बेईमानी का एक मौका है। ऐसा नहीं है कि सरकारें इस समस्या से अनजान हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं।

पिछले दिनों सरकार के स्तर पर परीक्षाओं में कदाचार को लेकर खूब चर्चा हुई। इसे रोकने और परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए संसद में एक बिल भी लाने की तैयारी चल रही है। अब इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बार-बार ऐसी खबरों से पूरे देश का मनोबल टूट जाता है। सरकर मेधावी युवा डाक्टरी से लेकर इंजीनियरिंग और अन्य विषयों की शिक्षा के लिए भी विदेश की तरफ देखने को मजबूर हो रहे हैं। हर साल देश के 10-12 लाख बच्चों का विदेश में शिक्षा के लिए पलायन हमारे लिए चेतावनी है। इससे न सिर्फ देश का बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है, बल्कि प्रतिभाओं से भी हम हाथ धो रहे हैं। चंद्रमा से लेकर सूर्य मिशन तक संचालित करने वाले हमारे देश के लिए बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षाएं कराना असंभव नहीं होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) हर साल करीब 12 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित करता है। रेलवे ने तो एक-एक करोड़ परीक्षार्थियों की परीक्षा ली है। आखिर एनटीए को परीक्षा आयोजित करता है। रेलवे ने तो एक-एक करोड़ परीक्षार्थियों की परीक्षा ली है। आखिर एनटीए ने इससे सबक क्यों नहीं सीखता? एक सवाल यह भी है कि क्या देश की हर समस्या का समाधान न्यायपालिका खासकर सुप्रीम कोर्ट ही निकालेगा? जब नीट-यूजी में हुई गड़बड़ी को लेकर लोगों ने शिकायत की तो कार्यपालिका और उसकी संस्थाओं ने पहले चुप्पी क्यों साध ली? राहत के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी?

इसमें दो राय नहीं कि मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में सख्ती से कार्यपालिका और नौकरशाही को दुरुस्त करना होगा। क्या शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी संस्थाओं की शोभा बढ़ाने और वेतन एवं पेंशन आदि सुविधाओं की हकदारी के लिए ही हैं? सरकार को चाहिए कि वह इन नकली सेवकों को भी कुछ सबक सिखाए। यदि नौकरशाही ठीक से काम करे तो ऐसा कोई कारण नहीं कि हर क्षेत्र में व्यवस्थागत सुधार न हो सके, लेकिन उससे पहले राजनीतिक सत्ता को भी अपने चाल-चलन को बदलना होगा। नीट-यूजी में गड़बड़ी को मोदी सरकार को एक खतरे की घंटी के रूप में लेने की जरूरत है। इस सरकार की प्रतिष्ठा बड़े और ठोस शिक्षा सुधारों से ही वापस लौट सकती है। ऐसे सुधारों में अब विलंब नहीं किया जाना चाहिए।

(भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे लेखक शिक्षाविद हैं)

response@jagran.com

समर्पण भाव

व्यक्ति जब अपने इष्ट, आराध्य, गुरु और किसी महापुरुष के समक्ष पूर्ण समर्पित होकर प्रणाम करता है तो उसमें लोभ, मोह, अहंकार, कामना और तृष्णा का त्याग-भाव दृष्टिगोचर होता है। कर्ता के समर्पण भाव से ही उसमें विनम्रता, शिष्टता, प्रेम, सद्भाव, सज्जनता, उदारता, पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता और दिव्यता की धारा बहती है। समर्पण का अभाव उद्दंडता, दुष्टता, अशिष्टता का प्रतीक है, जो मानव की संतता और सज्जनता में दीमक लगकर उसके स्वभाव को खोखला, प्राणहीन, शक्तिहीन एवं पतित बना देता है। इन नैतिक गुणों के अभाव में मानव जीवन धरती पर भार बन जाता है।

जब बूंद तालाब, नदी, समुद्र में स्वयं को समर्पित करती है तो वह बूंद नहीं रहती है। वह अपने अस्तित्व को मिटाकर तालाब, नदी, समुद्र की विशालता, महानता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब पतंग स्वयं को अपने स्वामी के हाथों में समर्पित करती है तो वह गगन में उड़ान भरती है। एक कठपुतली जब स्वयं को बाजीगर के हाथ में समर्पित करती है तो वह मात्र काठ का खिलौना नहीं रहती है, बल्कि मनुष्य की तरह तमाशा दिखाने लगती है। जब शिष्य स्वयं को गुरु को समर्पित करता है तो उसके जीवन में दिव्यता का संचार होता है। वह नरेंद्र से विवेकानंद, एक सिपाही से छत्रपति शिवाजी, विद्रोही से रत्नाकर, अंगुलीमाल से बौद्धभिक्षु बनकर धर्म-संस्कृति की पताका फहराने लगता है। एक नन्हा बीज जब खुद को धरती को समर्पित करता है तो वह उत्तरोत्तर विकसित होकर विशाल वट वृक्ष बनकर असंख्यों को छाया, हवा और ईंधन प्रदान करता है।

इस प्रकार समर्पण करते ही समर्थ की समस्त शक्तियों और गुणों का संचार उसमें होने लगता है। फिर नरक से स्वर्ग, तुच्छ से महान, बूंद से सागर, राई से पर्वत के बनने की यात्रा आरंभ हो जाती है। महानता के पथ पर अग्रसर होने के लिए यही समर्पण भाव स्वाग्रक सिद्ध होता है। मृण्मय से चिन्मय बनने की भी यात्रा समर्पण के बाद ही आरंभ होती है।

मुकेश ऋषि

ग्लोबल हुआ 'नमस्ते'

डा. मोनिका शर्मा

भारतीय जीवनशैली और संस्कृति से जुड़े रंग अब दुनियाभर में सम्मान और सहजता से अपनाए जा रहे हैं

बीते दिनों इटली में हुए जी-7 सम्मेलन में अभिवादन के लिए 'नमस्ते' की मुद्रा में जुड़े हाथ भारतीय संस्कृति की विशेष आभा बिखेरते दिखे। जी-7 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे देशों का समूह है। इस सम्मेलन में कई साझी चिंताओं पर विमर्श किया जाता है। ज्ञात हो कि भारत एक अतिथि देश के तौर पर इस सम्मेलन का हिस्सा बनता है। इस वर्ष भारत 11वीं बार जी-7 सम्मेलन में एक अतिथि देश के तौर पर शामिल हुआ था। इस बार सम्मेलन में इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी द्वारा भारतीय परंपरा के अनुसार नमस्ते कहकर मेहमानों का स्वागत करने का चौहिया दुनियाभर में छा गया। इसके बाद हर ओर भारतीय संस्कृति और परंपरा के रंगों की भी चर्चा होने लगी।

वस्तुतः भारतीय जीवनशैली और संस्कृति से जुड़े रंग अब दुनियाभर में सम्मान और सहजता से अपनाए जा रहे हैं। हिंदी भाषा, योग, परंपरागत खानपान और वैचारिक भावबोध तक, बहुत कुछ दुनिया के हर हिस्से में सराहा जा रहा है। इस सूची में अभिवादन का अंदाज 'नमस्ते' भी ग्लोबल हो चला है। हाथ जोड़कर अभिवादन करने के इस तरीके को योग ने भी खूब विस्तार दिया है। सही ढंग से नमस्ते करने से हृदय चक्र सक्रिय होता है। असल में झुकने की क्रिया यौगिक संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। यह मुद्रा शारीरिक विन्यास में ही नहीं, मन से भी सम्मान देने और विनम्र रहने के भाव से जुड़ी है। 'नमस्ते' संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ ''आपको प्रणाम करना'' या 'मैं आपको प्रणाम करता हूं'' है। दोनों हाथों को जोड़ सम्मान के साथ अभिवादन के रूप में इस मुद्रा का उपयोग किया जाता है।

आक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किए गए नमस्ते का अर्थ भारतीय संस्कृति में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन और विनम्रता प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले शब्द के रूप में बताया गया है। ज्ञात हो कि कोरोना के दौरान भी भेंट या विदा के समय हाथ जोड़कर अभिवादन करने की इस परंपरा की खूब चर्चा हुई थी। संक्रमण से बचाव के लिए हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करने का परंपरागत तरीका ज्यादा उचित माना गया था। देखा जाए तो शिष्टाचार का यह सुंदर तरीका असल में मानवीय भावबोध का सार्थक अंदाज है। नमस्ते का अर्थ सामने वाले ईंसान के मानवीय स्वरूप को नमन करने से भी जुड़ा है। वैश्विक स्तर पर संघर्ष, हिंसा और सहजता की विस्तार पाती परिस्थितियों में यह आवश्यक हो चला है कि विनम्रता और सहजता का भाव पोषित हो। मानवीय मूल्यों से जोड़ने वाली अभिवादन की यह मुद्रा हमारे मन-जीवन में ऐसे सार्थक भावों की उपस्थिति बनाए रखने में मददगार बन सकती है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जाति का जाल

'विकास पर हावी जाति की राजनीति' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में डा. सूर्यांल पांडेय ने जातिगत राजनीति को समाज के हर तबके के लिए खतरनाक बताते हुए समाज में सबका साथ सबका विकास वाली सूक्ति को जमीन पर चरितार्थ करने के लिए जरूरी सुझाव दिया, जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो सके। विकास की राह में जातिगत राजनीति एक बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो गई है। यह सच है कि हमारे समाज में जाति का प्रभाव गहरा है, लेकिन क्या हम इसे विकास की प्राथमिकता से ऊपर रख सकते हैं? आज का दौर ऐसा है जहां हमें आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास की सख्त जरूरत है। जातिगत समीकरणों में उलझकर हम न केवल अपनी विकास की गति को रोक रहे हैं, बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी नष्ट कर रहे हैं। चुनाव के समय जातिगत समीकरणों का बोलबाला रहता है। हर पार्टी अपने वोट बैंक को साधने के लिए जातिगत कार्ड खेलती है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन वर्गों को होता है, जो समाज के हाशिए पर हैं और जिनकी आवाज अनसुनी रह जाती है। यह स्थिति हमारे संविधान की मंशा के खिलाफ है, जो समानता और समृद्धि की बात करता है। जातिगत राजनीति के इस दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए आवश्यक है कि हम समाज में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार करें। हमें यह समझना होगा कि विकास और प्रगति ही हमारे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमें ऐसे नेताओं का चुनाव करना चाहिए, जो विकास को बात करते हों। समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाकर और जातिगत भेदभाव के खिलाफ जागरूकता फैलाकर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जातिगत राजनीति को पीछे छोड़ना होगा और एक समृद्ध समाज की दिशा में कदम बढ़ाना होगा।

इंद्रेसन मौर्या, मुंबई

सुशासन की राह में रोड़ा

भारत सदियों से जाति प्रथा का दंश झेला है। इस प्रथा के कारण ही भारत सैन्य बल में कमजोर रहा, जिसका फायदा विदेशी आक्रांताओं और बाद में अंग्रेजों ने उठाया। मगर चेतने के बजाय हमने विभिन्न तरीके से जाति प्रथा का सता हित में दोहन किया। जबकि होना यह चाहिए था कि इसे पाटने का प्रयास किया जाता। दुखद है, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं, संवैधानिक शासन प्रबल होता है, नया न्यायिक और आर्थिक ढांचा सामने आता है तब इस बुराई का खात्मा होना चाहिए था, हो भी रहा था। मगर इसे हवा देकर राष्ट्र निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जाता रहा। यह सही है कि जाति को राजनीतिक हथियार बना सत्ता प्राप्त करना भले आसान है। मगर यह सुशासन की राह में रोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की चार जातियों में देश के सभी धर्म और जाति के लोग समाहित हैं। इससे ही राष्ट्र का भला होगा। mukeshkr.m7542@gmail.com

जरूरी है एक राष्ट्र-एक चुनाव

हमारे देश में जिस तरह दलबदल की हवा चली है और राजनेता जिस तरह अवसरवाद के शिकार हो रहे हैं उसके लिए जरूरी हो जाता है कि देश में जल्दी से जल्दी एक राष्ट्र एक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो। अभी देश लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से मुक्त हुआ ही है कि देश के कुछ राज्यों के कुछ स्थानों पर उपचुनाव का बिगुल बजने के कारण वहां फिर से आचार संहिता लागू हो गई। भारत में 1952 से 1967 तक लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ करते थे, लेकिन 1971 में मध्यावधि चुनाव से यह सिलसिला टूट गया। अब एक बार फिर से एक साथ चुनाव की आवाज उठने लगी है। जब भी कहीं कोई परिवर्तन होता है तो जरूरी नहीं उसमें फायदा ही फायदा हो, थोड़ा-बहुत नुकसान भी जरूर होता है। लोकतंत्र का आधार ही चुनाव होते हैं, चुनाव प्रक्रिया में अगर कुछ कमियां हों तो उन्हें दूर करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत होता है। एक साथ चुनाव का अगर देश को फायदा होता है तो इस व्यवस्था को लागू करने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। raju09023693142@gmail.com

मेलबाक्स

उक्त स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संपादक-न्य. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रकाशक संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रकाशक संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

किसी संगठन की उपलब्धियां एक व्यक्ति के बजाय संयुक्त प्रयास का नतीजा होती हैं। -विंस लोंबार्डी

पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना ने करीब एक साल पहले ओडिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे की भयावह यादें ताजा कर दी हैं। बुनियादी ढांचे में सुधार जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी हादसों से सबक लेना भी है, ताकि व्यवस्थाओं को इस तरह सुधारा जाए कि भूलों की पुनरावृत्ति न हो।

सबक कब लेंगे

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ हुई एक मालगाड़ी की टक्कर ने, जिससे करीब नौ लोगों की मौत व चालीस से ज्यादा लोग घायल हुए, करीब एक साल पहले ओडिशा में हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस के भीषण हादसे की डरावनी यादें तो ताजा की ही हैं, रेल सुरक्षा की जरूरत को भी फिर से रेखांकित किया है। हालांकि अभी आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर होने की वजह क्या थी, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट बताती है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे की ही भांति ताजा दुर्घटना मुख्य रूप से सिग्नलिंग त्रुटि की वजह से हुई। उल्लेखनीय है कि सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस सोमवार की सुबह न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के नजदीक रंगपानी के पास खड़ी थी। यह टक्कर तब हुई, जब एक मालगाड़ी कथित तौर पर सिग्नल से आगे निकल गई और कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गई। दरअसल यह टक्कर, रेलवे सुरक्षा और दुर्घटना के संभावित कारणों को लेकर चिंता पैदा करती ही है, कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे की तरह, सिग्नलिंग और संचार प्रणालियों में संभावित विफलताओं की ओर भी इशारा करती है। कथित तौर पर टक्कर इसलिए हुई, क्योंकि मालगाड़ी का लोको पायलट शायद खराब मौसम की वजह से सिग्नल देख नहीं पाया और इस वजह से मालगाड़ी पूरी गति से कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इस घटना ने रेलवे की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, 'कवच' पर नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत पैदा की है। दरअसल, दिल्ली और गुवाहाटी रेल लाइन और पश्चिम बंगाल में कवच अभी लगा नहीं है। यह चिंतित करने वाली बात है कि वर्ष 2022 के बजट में जिस कवच योजना की शुरुआत हुई थी, वह फिलहाल देश के पूरे रेल नेटवर्क के मात्र दो फीसदी हिस्से में ही है। उल्लेखनीय है कि कवच को 'सिग्नल पास्ड एट डेंजर' (एसपीएडी) के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ट्रेनों के टकराव का एक प्रमुख कारण है।

कंचनजंगा एक्सप्रेस एक दैनिक ट्रेन है। ऐसे में, इस दुर्घटना ने रेल कनेक्टिविटी पर असर को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर चिकन नेक कारिडोर पर, जो पूर्वोत्तर शहरों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस संदर्भ में रेल सुरक्षा पर कैग की पिछली रिपोर्ट भी ध्यान देने योग्य है, जो पटरियों के रख-रखाव फंड के उचित इस्तेमाल न होने की बात उठाती है। बुनियादी ढांचे में सुधार, अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग और कर्मचारियों का समुचित प्रशिक्षण जरूरी हैं, लेकिन उतना ही जरूरी हादसों से सबक लेना भी है, ताकि व्यवस्थाओं को इस तरह सुधारा जाए कि भूलों की पुनरावृत्ति न हो।

क्या यह सिर्फ परिवार का झगड़ा है?

जब भी भाजपा की स्थिति थोड़ी कमजोर होती है, आलोचक संघ-भाजपा के बीच सत्ता-संघर्ष की कहानी गढ़ने लगते हैं। लेकिन, मोदी संघ का मुखौटा नहीं हैं और संघ भी भीतर से जानता है कि मोदी उसकी विचारधारा के सबसे अच्छे उत्पादों में से हैं।

शेखर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या गड़बड़ हुई है? वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन शायद संघ को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व ने नुकसान पहुंचाया है और वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने भाजपा के कई उम्मीदवारों के बारे में चेतावनियों की अनदेखी की, जिसके कारण वे हार गए, खासकर उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा, कहा गया है कि मोदी ने पिछले सात-आठ साल से संघ के नेताओं से सलाह लेना भी बंद कर दिया है।

मोदी की विराट शख्सियत ने संघ नेताओं के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि वे कोई मुद्दा उनके सामने उठाएं। यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकसभा में भाजपा के बहुमत हासिल नहीं करने पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा कि एक सच्चे सेवक को 'अहंकार' नहीं होना चाहिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपना काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि तीखे चुनाव प्रचार के दौरान 'मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया।' हालांकि संघ के भीतर के कई लोगों ने संकेत देने की कोशिश की कि उनकी टिप्पणियां केवल मोदी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर ही नहीं थीं।

आम तौर पर संघ रोजमर्रा के राजनीतिक मामलों से दूर दिखना चाहता है और वह 2025 में अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर अपना जनाधार बढ़ाने में व्यस्त है। कुछ संघ कार्यकर्ता राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय संगठन सचिव या संयुक्त संगठन सचिव के रूप में भाजपा के लिए काम करते हैं।

ये कार्यकर्ता पूर्णकालिक होते हैं और उन्हें 'प्रचारक' कहा जाता है। मोदी स्वयं संघ के प्रचारक थे और भाजपा संगठन में सचिव के पद पर थे। भाजपा और संघ के बीच प्रकटतः न तो हितों का टकराव रहा है और न ही सत्ता संघर्ष रहा है, क्योंकि वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। बताया जाता है कि संघ नेतृत्व समझता है कि राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं और भाजपा उनका पालन करने के लिए स्वतंत्र है। संघ न तो शासन-प्रशासन और न ही भाजपा की राजनीतिक गतिविधियों में दखल देने की बात कहता है। केंद्रीय भाव यह है कि वह वैचारिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और आगे भी निभाता रहेगा।

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान संघ ने चुप्पी साधे रखी, जबकि ऐसी खबरें भी आईं कि प्रचारक मतदाताओं को एकजुट करने में उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि भाजपा के बहुमत से चूक जाने के तुरंत बाद आलोचनात्मक स्वर उभरे। भागवत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई, जब इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि क्या संघ ने वास्तव में भाजपा से दूरी बना ली है और चुनाव के दौरान दिल से उसका समर्थन नहीं किया? नतीजों के बाद अपनी पहली टिप्पणी में संघ प्रमुख ने प्राथमिकता के आधार पर मणिपुर संघर्ष खत्म करने और सरकार तथा विपक्ष के बीच आम सहमति की आवश्यकता पर बल दिया था।

आलोचनाओं का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। संघ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि भगवान राम ने एक 'अहंकारी' पार्टी को लोकसभा में बहुमत पाने से रोक दिया, जो 'रामभक्त' होने का दावा करती थी। फिर एक संघ विचारक रतन शारदा ने संघ के मुखपत्र '*ऑर्गेनाइजर*' में लिखा कि चुनावी नतीजे आति आत्मविश्वासी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 'रियलिटी चेक' थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेतृत्व ने चुनाव में सहयोग के लिए संघ के स्वयंसेवकों से संपर्क नहीं किया। संघ के कई नेता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से नाराज थे, जिन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है। उनका मानना था कि इससे संघ कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है ।

देखा जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के विपरीत मोदी को पिछले दस वर्षों में संघ से कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। उन्होंने संघ और भाजपा के लक्ष्यों को पूरा किया, जिनमें अनुच्छेद 370 हटाना और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। वाजपेयी के 'उदारवादी' रवैये पर केएन गोविंदाचार्य ने टिप्पणी करते हुए उन्हें संघ का मुखौटा कहा था, (हालांकि वह लगातार इस बयान से इन्कार करते रहे)। जाहिर है, वाजपेयी ने उस टिप्पणी के लिए गोविंदाचार्य को कभी माफ नहीं किया और धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार किया। और फिर, गोविंदाचार्य को इस तरह निर्वासित कर दिया कि वे कभी वापस नहीं आए।

लेकिन मोदी संघ का मुखौटा नहीं हैं। वास्तव में वे संघ की विचारधारा के सबसे अच्छे उत्पादों में से एक हैं। साथ ही, मोदी एक ऐसे नेता हैं, जो 2024 के नतीजों को भूलने वाले नहीं हैं। वे विस्तार से पता लगाएंगे कि नतीजे भाजपा के लिए अच्छे क्यों नहीं रहे। इसलिए गहनता से देखें, तो मोदी और संघ के बीच कोई मूलभूत द्वैध नहीं है।

1980 के दशक में संघ ने मोदी को भाजपा को सौंपा था और वह प्रधानमंत्री बने। हां, यह जरूर है कि भाजपा के साथ मोदी की छवि 'लार्जर देन लाइफ' है। ऐसे में, भले ही भाजपा लोकसभा में बहुमत पाने से चूक गई हो, लेकिन पार्टी पर उनकी पकड़ और मतदाताओं पर उनके प्रभाव को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता।

दरअसल, जब भी भाजपा की स्थिति थोड़ी कमजोर होती है, तो बाहर-भीतर के आलोचक संघ-भाजपा के बीच सत्ता-संघर्ष की काल्पनिक कहानी गढ़ने लगते हैं। संघ अपने 36 संगठनों के माध्यम से 60,000 दैनिक शाखाएं और दो लाख से ज्यादा कल्याणकारी परियोजनाएं चलाने में व्यस्त है। वह 2025 में अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर आधार मजबूत करने में जुटा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं की संख्या काफी बढ़ गई है और इसमें नेताओं की एक बड़ी जमात है।

अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, मोदी जैसे मजबूत नेता के नेतृत्व में पार्टी खुद को संभालने में सक्षम है और आने वाले दिनों में पार्टी को अपनी दिशा खुद तय करनी है। चुनाव नतीजों के कारण अगर कुछ सुधार की जरूरत पड़ी, तो वह भाजपा खुद करेगी। मोदी इतने सख्त हैं कि खुद के साथ-साथ विफलताओं के लिए जिम्मेदार हर तत्व को कसौटी पर कसेंगे। अंततः जो लोग संघ-भाजपा में सत्ता संघर्ष की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें निराशा होगी।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

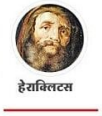

हैराक्लिटस

नदी का निरंतर प्रवाह परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाता है। अगर हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते हैं, तो सामने परेशानियों का पहाड़ नजर आता है। नदी पहाड़ को नहीं बदलती, वह अपना रास्ता खुद बना लेती है।

जीवन जीने की तरकीब परिस्थिति के अनुकूल ढलना

दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। भले ही कुछ चीजें स्थायी लगती हों, लेकिन ऐसा है नहीं। हकीकत में देखेंगे, तो पाएंगे कि चीजें, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। और यह बात पूरे ब्रह्मांड के लिए लागू होती है। क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता चला आ रहा है? दरअसल, इसके पीछे एक शक्ति काम करती है। यह सर्वव्यापी शक्ति ही निरंतर परिवर्तन के साथ जुड़ी है। इसलिए हम एक निरंतर बदलती दुनिया में रहते हैं। अगर हम जीवन की नदी की सतह पर रहें और इसकी वास्तविक गहराई को न देखें, तो यह लगभग असंभव है। मनुष्य का जीवन भी नदी की तरह ही है। निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति और परिवर्तन, दोनों साथ चलते हैं। कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में दो बार नहीं उतरता, क्योंकि यह वही नदी नहीं है और वह वही व्यक्ति नहीं है। जो नदी पहले दिन जैसी दिख रही थी, वह अगले दिन वैसी नदी तो नहीं रह जाएगी। हर दिन सारा पानी नया आ रहा है और बहता हुआ निकल जा रहा है। नदी कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। इसमें उतार-चढ़ाव आते रहते हैं।

इसकी चौड़ाई और गहराई बदलती रहती है। कभी-कभी एक नदी उफान पर आ जाती है और अपने तटबंधों को तोड़ देती है। यह एक सतत होते रहने वाला परिवर्तन है। परिवर्तन का ऐसा ही चक्र हम अपने जीवन में भी देखते हैं। मनुष्य के जीवन में भी ऐसे उतार-चढ़ाव, सुख-दुख, प्रेम-पीड़ा आदि के दौर आते-जाते रहते हैं। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला बेहद खुश है, लेकिन बहुत संभव है कि दुख की किसी धारा का भी उसके भीतर प्रवाह बना हुआ हो। इसलिए नदी का निरंतर प्रवाह हमें परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाता है। एक सुखी जीवन का रहस्य इसी में छिपा है। अगर हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते हैं, तो सामने परेशानियों का पहाड़ ही नजर आता है। इसलिए जीवन जीने की तरकीब है कि प्रवाह के साथ चलना यानी परिस्थितियों के अनुकूल ढलना। हर नदी एक छोटी धारा के रूप में शुरू होती है। फिर चलते-चलते उसमें और दूसरी नदियों का मिलन होता जाता है और इस प्रकार एक स्रोत से निकली छोटी-सी धारा बड़ी नदी बन जाती है। धीरे-धीरे उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। पहाड़ों, जंगलों और सभ्यताओं के बीच से नदियां अपना रास्ता बनाती हैं और लगातार अपने अंतिम गंतव्य यानी महासागर की ओर बढ़ती हैं। ठीक यही स्थिति मनुष्य की जीवन यात्रा की है। जीवन की यात्रा में भी चुनौतियां आती हैं, मोड़ और बाधाएं आती हैं। लेकिन इन्सान कभी रुका नहीं। मानव इतिहास बताता है कि धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर आज तक हम कैसे बढ़ते चले गए और अपने लक्ष्यों की खोज में आज भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं।

तो रास्ता बदल लें

सूत्र

जब नदी को किसी ऊंचे पहाड़ जैसी बाधा का सामना करना पड़ता है, तो नदी पहाड़ को तोड़ने पर जोर नहीं देती। इसके बजाय वह उसके चारों ओर बहने लगती है या अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। मनुष्य के लिए यह बड़ा संदेश है। जीवन में जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति या बाधा आती है, जिसे हम बदल नहीं सकते, तो हमें उस बाधा को बदलने की इच्छा रखने के बजाय उसमें ही रास्ता निकाल लेना चाहिए।

दूसरा पहलू

पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त लेखिका जेनिफर इगन का उपन्यास *द कैंडी हाउस* नीदरलैंड में डच के बजाय अंग्रेजी भाषा में ज्यादा बिका।

यूरोप के देशों में छा रही है अंग्रेजी

पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त लेखिका जेनिफर इगन कुछ साल पहले जब अपने नए उपन्यास *द कैंडी हाउस* के प्रमोशन के सिलसिले में नीदरलैंड्स में थीं, तब वहां उन्होंने एक नई चीज देखी। वहां इगन के जितने भी प्रशंसक उनके दस्तखत के लिए इकट्ठा हुए थे, उन सबके पास उपन्यास की अंग्रेजी कॉपी थी। यही नहीं, जिनके पास उपन्यास की डच कॉपी थी, वे लेखिका के पास जैसे माफी मांगने की मुद्रा में खड़े थे। इगन का आकलन सही था। *द कैंडी हाउस* के डच प्रकाशक के मुताबिक, नीदरलैंड्स में इसकी जितनी बिक्री हुई, उसमें अंग्रेजी कॉपी की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत थी।

क्लैयरे मोजेज

यूरोप में अंग्रेजी के पाठक बढ़ रहे हैं। यूरोपीय देशों में ज्यादातर पाठक स्थानीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी और अमेरिकी किताबें मूल भाषा में ही खरीदने लगे हैं।

यह तथ्य है कि यूरोप में अंग्रेजी के पाठक बढ़ रहे हैं। यूरोपीय देशों में ज्यादातर पाठक स्थानीय भाषाओं के बजाय अंग्रेजी और अमेरिकी किताबें मूल भाषा में ही खरीदने लगे हैं। स्कैंडिनेवियन देशों, नीदरलैंड्स और खासकर जर्मनी के बारे में यह सच है, जो दुनिया में पुस्तकों के सबसे बड़े बाजारों में से है। इससे इन देशों के प्रकाशक तथा अमेरिका और ब्रिटेन के एजेंट थोड़े परेशान हैं, क्योंकि इससे अनूदित पुस्तकों का बाजार सिकुड़ जाएगा, जिससे लेखकों को कम पैसे तो मिलेंगे ही, दूसरे देशों में उनकी किताबों के अनुवाद की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी।

विदेश में बिकने वाली अंग्रेजी किताबें ब्रिटिश व अमेरिकी प्रकाशकों द्वारा छापी गई सस्ती पेपरबैक किताबों में, और जो यूरोप के अलग-अलग देशों में स्थानीय भाषाओं में अनूदित किताबों की तुलना में बहुत ही सस्ती हैं।

विदेश में बिकने वाली अंग्रेजी किताबें ब्रिटिश व अमेरिकी प्रकाशकों द्वारा छापी गई सस्ती पेपरबैक किताबों में, और जो यूरोप के अलग-अलग देशों में स्थानीय भाषाओं में अनूदित किताबों की तुलना में बहुत ही सस्ती हैं।

'लोगों को उसी भाषा में पढ़ना चाहिए, जिस भाषा में उसे सहूलियत हो। लेकिन एक्सपोर्ट एडिशन सस्ते होते हैं', नीदरलैंड्स की एक प्रकाशक एलिक लेटिंगा कहती हैं। हाल के वर्षों में अंग्रेजी किताबों की बिक्री बढ़ने का एक कारण यह है कि किताबें अब सोशल मीडिया, खासकर टिकटॉक, में वायरल हो जाती हैं। नीदरलैंड्स के कुछ प्रकाशकों का कहना है कि वे युवा भी अंग्रेजी भाषा की किताबें खरीदना चाहते हैं, जो डच भाषी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बुकटॉक पर, जहां वे ये किताबें देखते हैं, इसके बारे में पोस्ट करना चाहते हैं। हालांकि इससे निपटने के लिए कुछ डच प्रकाशकों ने डच भाषा में अनूदित किताबों के कवर को अंग्रेजी के कवर के अनुरूप अंग्रेजी शीर्षक के साथ छापना शुरू किया है। लेकिन इससे यूरोपीय युवाओं में अंग्रेजी के प्रति जुनून को कम नहीं किया जा सकता।

-साथ में एलिजाबेथ ए हैरिस।

©The New York Times 2024

आंकड़े

चीन से आगे ब्रिटेन

चीन को पीछे छोड़कर ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है।

नोट: आंकड़े अरब डॉलर में हैं। | स्रोत: DoC

महर्षि ऋभु ने पुलस्त्य ऋषि के पुत्र निदाघ से कहा कि यदि वेदों को संपूर्णतः रट जाएं और वस्तु तत्व का ज्ञान न हो, तो वह किस काम का?

ऋभु ने निदाघ को दिया आत्मज्ञान

अंतर्यात्रा
संकलित

महर्षि ऋभु एक दिन पुलस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने देखा कि पुलस्त्य का पुत्र निदाघ वेदाध्ययन कर रहा है। महर्षि ऋभु ने निदाघ से कहा कि इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्णतः रट जाएं और वस्तु तत्व का ज्ञान न हो, तो वह किस काम का? इसलिए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो।

इसके बाद निदाघ ऋभु के साथ रहने लगे। बाद में महर्षि ने निदाघ से कहा, अब तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो। निदाघ का विवाह हुआ और गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। लंबे समय बाद महर्षि ऋभु निदाघ के पास पहुंचे। निदाघ ने महर्षि का आदर सत्कार किया और उनको भोजन कराया, लेकिन लंबे समय बाद मिलने की वजह से वह अपने गुरु को पहचान नहीं सके। निदाघ ने पूछा, महाराज! आप भोजन से तृप्त हो गए क्या? और कहां रहते हैं? महर्षि ने कहा कि भूख और प्यास प्राणों को लगती है। मैं प्राण नहीं हूं। जब भूख-प्यास मुझे लगती ही नहीं, तब तृप्ति-अतृप्ति क्या बताऊं?

स्वस्थता ना तृप्ति मन के ही धर्म हैं। आत्मा इनसे पृथक है। रहने के संबंध में जो पूछा, उसका उत्तर सुनो। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है। उसका आना-जाना नहीं बनता। मैं न आता हूं, न जाता हूं और न ही किसी एक स्थान पर रहता ही हूं। इसलिए अनात्म वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने आप में स्थिर हो जाओ। निदाघ ने महर्षि के चरणों में अपना सिर रख दिया। बाद में उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा गुरु ऋभु हूं।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 9 अप्रैल, 1950

भयंकर रेल दुर्घटना में सौ से भी ज्यादा मरे

गाड़ी नदी में गिर पड़ी
४० यात्रियों के डिब्बे डूब गये
बेल्जियम के इतिहास में दुखद घटना
आज्ञाकारी बनने के लिए दुःखद सबक
नकली पर मिट छापने का प्रेस पकड़ा गया

बेल्जियम से मिले समाचार से ज्ञात हुआ है कि ब्रुसेल्स से 100 मील दूर एक सवारी गाड़ी पुल से नदी में गिर गई। इसमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। गाड़ी के 40 डिब्बे पानी में डूब हुए हैं। यह बेल्जियम के इतिहास की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है।

जनजातीय हितों की अनदेखी न हो

लद्दाख में करीब 90 फीसदी जनसंख्या जनजातियों की है, जिन्हें पर्यावरण संकटों के साथ विस्थापन का दर्द भी झेलना पड़ा।

सीबीपी श्रीवास्तव | मुद्दा

बाजारवाद और भौतिकता के दौर में अगर स्थिरता के साथ विकास करना है, तो प्रकृति के साथ-साथ संस्कृति का संरक्षण भी अनिवार्य है। लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की वजह भी यही है। वहां के लोगों का मानना है कि लद्दाख के प्राकृतिक पर्यावरण और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए स्थानीय परिषदों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, अन्यथा बाह्य हस्तक्षेप से लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति के क्षरित हो जाने की आशंका बनी रहेगी।

लद्दाख में करीब 90 फीसदी जनसंख्या जनजातियों की है। इनमें गुज्जर, बकरवाल, बोट, चंगपा, बाल्टिस और पुरिगपा जनजातियां प्रमुख हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव और संघर्ष के कारण इन्हें विस्थापित होना पड़ा है, जिससे इन्हें सांस्कृतिक विलगाव और सामाजिक-आर्थिक बहिष्करण जैसी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है। लद्दाख में पर्यावरणीय समस्याएं भी गंभीर हैं।

वर्ल्ड वेदर ऑनलाइन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण लद्दाख में वर्षा चक्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। लद्दाख के चट्टानी इलाके में बारिश के पानी के संग्रहण की कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह इसे बाढ़ के रूप में नीचे की ओर धकेलता है। समझना होगा कि लद्दाखवासियों के लिए छठी अनुसूची क्यों जरूरी है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए संविधान ने संघ को अनुच्छेद 244 में उत्तरदायी बनाया है। अनुसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इसके लिए पांचवीं अनुसूची बनाई गई है, जबकि, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के वे क्षेत्र, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए जिला या क्षेत्रीय स्वायत परिषदों का प्रावधान करते हैं, जनजातीय क्षेत्र कहलाते हैं। ये चार राज्य छठी अनुसूची में रखे गए हैं। छठी अनुसूची में स्वायत्त परिषदों की स्थापना का प्रावधान है, जिनके पास इन क्षेत्रों पर स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां होती हैं।

छठी अनुसूची के तहत 10 स्वायत परिषदें हैं, जिनमें असम, मेघालय और मिजोरम में तीन-तीन और त्रिपुरा में एक शामिल है। प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) की स्थापना की जाती है, जबकि क्षेत्रीय परिषदों (आरसी) की स्थापना वहां की जाती है, जहां मुख्य जनजाति के अलावा अन्य जनजातियों की महत्वपूर्ण आबादी होती है।

पांचवीं अनुसूची उस राज्य के राज्यपाल को, जहां अनुसूचित क्षेत्र स्थित हैं, संसद या विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून को रोकने या संशोधित करने और उन क्षेत्रों में सुशासन के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इसमें राज्यपाल को सलाह देने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषदों की भी स्थापना का प्रावधान है। 1996 में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम पारित किया गया, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में बस्ती स्तर की ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का उल्लेख है। प्रश्न यह है कि लद्दाख पांचवीं अनुसूची के बदले छठी अनुसूची में शामिल क्यों होना चाहता है। जम्मू-कश्मीर के 2019 में पुनर्गठन के पहले लद्दाख को अनुच्छेद 370 और 35-ए के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त था।

पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र बिना किसी विधायी शक्ति के पंचायती राज और जिला परिषद द्वारा शासित होते हैं, वहीं छठी अनुसूची में क्षेत्रों की देखरेख स्वायत्त जिला परिषदों द्वारा की जाती है। लद्दाख में पहले से ही स्वायत पर्वतीय विकास परिषदें हैं और उन्हें छठी अनुसूची में एकीकृत करने से उन्हें समान शक्तियां मिलेंगी। भारत के संविधान में जिस प्रकार का राजनीतिक ढांचा बनाया गया है, उसमें राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इनकी पहचान की रक्षा कर ही राष्ट्र की अखंडता को सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत में संघ शासित क्षेत्रों के गठन का आधार मूलतः सांस्कृतिक रहा है। हालांकि कई ऐसे क्षेत्रों की स्थापना सांस्कृतिक कारकों के साथ-साथ अन्य कारकों के आधार पर भी की गई है जैसे, दिल्ली (राजनीतिक), पुदुचेरी (भौगोलिक) आदि। लद्दाख की संस्कृति की रक्षा तो महत्वपूर्ण है ही, यह क्षेत्र सामरिक अथवा राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में यहां विरोध प्रदर्शन की गंभीरता पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 18 जून 2024

स्वतंत्र नीति

स्विट्ज़रलैंड में हुआ अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द से जल्द समाप्त करने की इच्छा और जरूरत को रेखांकित करते हुए संपन्न हुआ। हालांकि सम्मेलन में शामिल भारत जैसे कई देशों के साझा बयान पर हस्ताक्षर न करने से यह स्पष्ट हो गया कि सम्मेलन की भावना चाहे जितनी भी नेक रही हो, शांति का लक्ष्य हासिल करने में अभी ढेरों व्यावहारिक दिक्कतें हैं।

पॉजिटिव संकेत | इस सम्मेलन में 90 से ज्यादा देशों का शामिल होना एक पॉजिटिव संकेत कहा जाएगा। इससे यह साफ होता है कि दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा यूक्रेन में शांति स्थापित होने की जरूरत को कितनी शिद्दत से महसूस कर रहा है। मगर शांति स्थापित होने की इच्छा जताना एक बात है और शांति स्थापित हो जाना बिल्कुल अलग बात।

यूक्रेन शांति सम्मेलन में भारत

एकतरफा प्रयास | ध्यान रहे यूक्रेन की पहल पर आयोजित इस शांति सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। रूस इसे व्यर्थ की कवायद करार भी दे चुका है। ऐसे में सम्मेलन के साझा बयान में कही गई बातें सांकेतिक महत्व की ही मानी जाएंगी। व्यवहार में इनका कोई मतलब तभी हो सकता है जब युद्ध में शामिल दोनों देश इसे स्वीकार करने पर सहमत हों।

शिरकत का तर्क | भारत ने अपने रुख से भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति पर कायम है। गौर करने की बात है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही चीन और भारत के रुख पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही हैं। चीन स्पष्ट तौर पर रूस के साथ खड़ा दिखता रहा है। लेकिन भारत ने साफ किया कि वह शांति का पक्षधर है। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पूतिन को भी साफ-साफ कह चुके हैं कि यह युद्ध का दौर नहीं है। इस बार भी जहां चीन सम्मेलन से दूर रहा, वहीं भारत ने बेहिचक सम्मेलन में शिरकत की, लेकिन स्पष्ट किया कि वह किसी भी एक पक्ष में खड़ा दिखने के बजाय दोनों युद्धरत देशों के बीच बातचीत और सहमति के प्रयासों को ज्यादा तवज्जो देता है।

धूप-छांव

किरदार किस्सों के

प्रणव प्रियदर्शी

बचपन में जो चीजें सबसे ज्यादा मजे देती थीं, उनमें नानी की कहानियों का स्थान शायद सबसे ऊपर था। तरह-तरह के किस्से होते, जिनके रचने वालों की कल्पनाशीलता आज भी चकित कर देती है। भूत-प्रेत तो उन कहानियों में आते ही, साधुओं और ऋषि-मुनियों के चमत्कार भी कम नहीं होते। हंसी-मजाक के मौके तो पूछिए मत। मगर इन सबके साथ ही, थोड़ा छूपा हुआ एक फैक्टर भी इनमें होता जिसका हम पर प्रभाव बिल्कुल सीधा होता था। वह था इन कहानियों में निहित मूल्यबोध। राजकुमार इन कहानियों का वीर नायक होता, वह प्रेम की खातिर तमाम तरह के जोखिम उठाता, मगर उसे मदद मिलती या तो दीवान यानी मंत्री के बेटे से जो उसका दोस्त होता था या फिर जंगल में रहने वाले किसी साधु-तपस्वी से जिसका समाज और शासन में निहित हायरार्की से कोई रिश्ता नहीं होता था। अक्सर इन कहानियों में नौकरों के बड़े सशक्त किरदार आते जो अपनी चतुराई से किसी अपमान का बदला लेते या सोशल हायरार्की में ऊपर बैठे तबकों की सोच को निशाना बनाते दिखते।

मसलन, एक पंडित जी थे जो अपने नौकर को इस बात के लिए दुतकारते रहते थे कि वह उनके जैसे निष्णात विद्वान के करीब रहते हुए भी संस्कृत नहीं बोल पाता। नौकर चुपचाप उनकी दुतकार सह लेता लेकिन कभी संस्कृत में बोलने की कोशिश नहीं करता। पंडित जी के पास आने-जाने वालों से सहज देसी जुबान में ही बात करता था। पंडित जी इस पर भी कुढ़ते कि उनकी बात का उस पर कुछ असर नहीं होता। खैर, एक दिन पंडित जी उसके साथ किसी जजमान के यहां जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी, तो एक कुएं पर ठहर गए। वहां रखी बालटी से पानी भर नौकर उन्हें पिलाने लगा तो पंडित जी का पैर फिसला और वह कुएं में गिर गए। पानी में डूबते-उतराते पंडित जी ने चिल्लाकर कहा, मुंह क्या देखते हो लोगों को बुलाओ मदद के लिए।

अब नौकर ने, जो आम तौर पर देसी जुबान में ही अपनी बात कहता, इस गंभीर संकट के वक्त संस्कृत बोलना शुरू किया। वह इधर-उधर भागते हुए चीख-चीख कर कह रहा था, 'यौ उपस्य से गिरला कूपस्य में, कश्चैत ढोबे वापस्य यौ वापस्य यौ' (वे ऊपर से गिर गए कुएं में और कर रहे हैं बाप रे बाप)। नीचे मौत से संघर्ष करते पंडित जी ने सिर पीट लिया कि किस घड़ी में मैंने इससे संस्कृत बोलने को कहा था, चिल्ला कर बोले, 'अरे मोली मारो संस्कृत को, अभी तो अपनी जबान में बोलो कि लोग बात समझ सकें।' कहानी हमें हंसी में लोटपोट होते छोड़, इसी बिंदु पर समाप्त हो जाती थी। पता भी नहीं चलता था कि कब अभिव्यक्ति की सहजता का पाठ हमारे अंदर दर्ज हो गया।

बोल वचन

धमधूसर राजा

राहुल पाण्डेय

अंधेर नगरी-चौपट राजा की कहावत बहुत पुरानी है। लेकिन इसका एक और वर्जन भी प्रचलित है- अंधेर नगरी-धमधूसर राजा। धमधूसर किसी चौपट राजा से कम नहीं होता। उसमें न तो अक्ल होती है, न ही शक्ल। यह शब्द अवधी से लेकर बुंदेली, मगही और मैथिली तक विराजमान है। सभी जगह इसका अर्थ एक ही है, ऐसा शख्स, जो

Subrata Dhar

भद्दा, मोटा, स्थूल और बेडौल है। लेकिन इतने से अर्थ पूरा नहीं होता। धमधूसर की अक्ल भी उसकी तरह होती है। बेवकूफी की बात पर वह बार-बार लड़ता रहता है। इसी अर्थ को पूरा करने के लिए अवध से लेकर मिथिला तक चौपट राजा वाली कहावत में धमधूसर राजा भी जोड़ते हैं। धमधूसर कोई आज का शब्द नहीं है। यह शब्द और नहीं तो कम से कम 400 साल पुराना है। तुलसीदास के जमाने के भी पहले का। कह सकते हैं कि चौपट शब्द के आने से पहले से ही धमधूसर सब कुछ चौपट करने पर उतारू था। कवितावली में तुलसीदास लिखते है, गुन ज्ञान-गुमान भभेरि बड़ी, कलपद्रुम काटत मूसर को। कलिकाल विचार अचार हरो, नहि सूझै कछू धमधूसर को। यानी ज्ञान के अहंकार में विचार इस तरह से नष्ट हो चुके हैं कि कलयुग में कौन बड़ा है या कौन छोटा, धमधूसर यानी बेवकूफ को कुछ नहीं दिखाई देता। जाहिर है, धमधूसरो से तुलसीदास भी काफी परेशान रहा करते थे। अंग्रेजी में इसका ऑप्शन flabby या फिर flaccid मिलता है। दिक्कत यह है कि इसमें धमधूसर की वह अक्ल और अहंकार नहीं दिखता, जो सदियों पहले तुलसीदास ने देख लिया था, और दर्ज भी कर दिया था।

जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, उसे देखते हुए खुले में काम करने वालों के बारे में सोचना होगा

हीटवेव और बढ़ेगी, कैसे हो गर्मी से बचाव

चंद्रभूषण

दिल्ली के मुंगेशपुर में 52.9 डिग्री सेल्सियस तापमान को इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने खारिज कर दिया। IMD ने कहा है कि इतने ऊंचे तापमान का कारण सेंसर की खराबी या कोई लोकल फैक्टर है। अगर सेंसर की खराबी के कारण गलत डेटा आया है तो इसे रिजेक्ट करना चाहिए। अगर यह लोकल फैक्टर के कारण है तो उसे नामंजूर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लोकल फैक्टर के कारण मुंगेशपुर में तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो वह सही है। इसे हटा दें, तो भी इस साल दिल्ली के तापमान ने रेकॉर्ड तोड़ा है। 28 मई को नरेला में 49.9 डिग्री तापमान रेकॉर्ड किया गया।

टूट रहे हैं रेकॉर्ड | हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि तापमान के रेकॉर्ड दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में टूट रहे हैं। चाहे आप मुंबई को लीजिए या हैदराबाद, बेंगलुरु को। हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है कि गर्मी से कैसे लोगों की जिंदगी, उनकी जीविका बचाई जाए क्योंकि हीटवेव बढ़ने ही वाली है।

2023 सबसे गर्म | वैश्विक स्तर पर 2023 सबसे गर्म साल था। 2023 का तापमान 1850, जिसे हम पूर्व-औद्योगिक युग मानते हैं, की तुलना में 1.48 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। 2023 भारत का भी दूसरा सबसे गर्म साल था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में सभी देशों ने ग्लोबल वॉर्मिंग को 1.5 डिग्री पर लाने की सहमति जताई थी, लेकिन 2023 में तापमान 1.4 डिग्री बढ़ गया। ऐसे में कुछ सालों के अंदर 1.5 डिग्री के एग्रीमेंट का टूटना तय है।

गर्मी बनी आफत

- लोकल फैक्टर से बढ़ता है तापमान
- हीटवेव से बड़ा आर्थिक नुकसान
- अब चाहिए डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम

उमस भी बताए IMD | सिर्फ तापमान का ही रेकॉर्ड नहीं टूट रहा। उमस भी बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों से मेरी संस्था ने IMD से बार-बार गुहार लगाई कि हीटवेव में यह सिर्फ तापमान ना बताए, बल्कि तापमान और उमस मिलाकर बताए। पिछले साल से IMD ने नया आंकड़ा रिलीज करना शुरू किया है, जिसे Feels Like तापमान कहते हैं जो गर्मी और नमी का एक संयोजन है।

Feels Like तापमान अधिक | अगर Feels Like तापमान 45 डिग्री से ज्यादा होता है तो खुले में काम करने वाले मजदूरों के लिए उसे बेहद खतरनाक माना जाता है। अगर यह तापमान 55 डिग्री से ऊपर चला जाए तो वह असहनीय स्तर है। तब बिना एयर कंडिशनर (AC) के रहना खतरनाक माना जाता है। मई में ही दिल्ली का Feels Like तापमान कई स्टेशनों पर 55 डिग्री को पार हो चुका है। बाहर शहरों में भी यही हाल है।

बिगड़ेंगे हालात | अभी हम जो तापमान या हीटवेव देख रहे हैं वह एक ट्रेलर है। अभी पूरी पिक्चर आई नहीं है। पिछले कुछ साल के अध्ययनों का मानना है कि हीटवेव भारत के लोगों की जिंदगी, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी पड़ेगी। अगर ग्लोबल वॉर्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाती है तो साल में कम से कम 150 दिन लोग बाहर काम नहीं कर सकेंगे। 80-90% जो हमारे देश में काम करने वाले लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में हैं। अगले कुछ सालों में इन पर हीटवेव का दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा।

AI Image

तोड़ना होगा चक्र | हीटवेव के बढ़ते दुष्प्रभाव को कम करने के लिए लिए हम क्या करें? लोग यही कहेंगे कि सब जगह AC लगाइए। हर जगह AC लगाना सही हल नहीं है। यह एक समस्या है। इसमें बहुत ज्यादा बिजली की खपत होती है। डेढ़ टन का फाइव स्टार AC पंखे से 30 गुना ज्यादा बिजली कंस्यूम करता है। अगर यह बिजली कोयले से बन रही है तो उससे ग्रीनहाउस गैस बढ़ेगी। लिहाजा, जलवायु परिवर्तन और तेज होगा, हीटवेव भी बढ़ेगी। यह एक चक्र है। जितना AC इस्तेमाल करेंगे, उतनी बिजली खपेगी, उतना ही ग्रीनहाउस गैस एमिशन होगा और उतनी ही ग्लोबल वॉर्मिंग।

बढ़ता खतरा | हमें पहले ऐसे तरीके अपनाने चाहिए, जिनसे AC जैसी चीजों की जरूरत ना पड़े। शहरों में पेड़ लगाएं, तालाबों को पुनर्जीवित करें, ताकि शहर ठंडे रहें। 'कूल हाउस' बनाएं, यानी ऐसे घर जो ठंडे रहें। इनमें ईको फ्रेंडली सामग्री इस्तेमाल हो, कमरे हवादार हों, और छत पर छांव हो। 'कूल रूफ' भी बहुत अच्छा तरीका है। छत को सफेद रंग से रंगने से घर के अंदर का तापमान 2-4 डिग्री कम हो जाएगा।

कूलिंग सिस्टम | फिर, हमें 'डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम' (DCS) जैसी चीजों इस्तेमाल करनी चाहिए। ये सिस्टम पाइपलाइन से ठंडा पानी इमारतों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि खाना पकाने के लिए गैस पहुंचती है। AC की तरह यह ठंडा पानी कमरों की हवा को ठंडा करता है। DCS बहुत ज्यादा एनर्जी बचाता है और जहरीली गैसों का इस्तेमाल नहीं करता। इससे कूलिंग का खर्च भी कम हो जाएगा, जिससे आम आदमी के लिए भी ठंडा रहना मुमकिन हो जाएगा। हमें सिर्फ ऐसे AC इस्तेमाल करने चाहिए जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हों। इसके लिए AC की एनर्जी लेबलिंग में बदलाव करना होगा, ताकि लोग ज्यादा एफिशिएंट AC ही खरीदें।

समग्र योजना | आखिरी बात, हर शहर में गर्मी से बचने और सबको ठंडक देने के लिए एक योजना बनानी होगी। यह जरूरी है ताकि शहर के लोगों और अर्थव्यवस्था को गर्मी के असर से बचाया जा सके। यह एक छोटी सी शुरुआत है। गर्मी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, और हमें इस खतरे से पहले ही तैयार हो जाना चाहिए।

(लेखक iForest के CEO हैं)

सिकंदर का क्वालिटी नई देखने का भिड़!

दीपक पाचपोर

अबी अपुन उस दिन अपना स्पेश्यल फ्रेंड बाबूराव का साथ गप्पा मारता बईठेला। अपुन उसकूं बोला- 'भिड़, तुम जानताए कि इलेक्शन का मचमच खतम हूएला। अबी अपुन थोड़ा शांत होके घर का कुछ काम सलटाएंगा।' बाबूराव बोले तो एकदम हैराण! वो क्या पूछेला- 'तुम कोई नया धंधा सुरु करेंगा क्या?' अपुन कहेला- 'नईं, बाबूराव! इस उमर में धंधा करेंगा? अपुन जिस धंधा कूं हात लगाएंगा उसका वाट लग जाएंगा। घर का बात करताए। छोकरी का वास्ते कोई अच्छा छोकरा देखने का काम भौत दिन से पेंडिंग गिरेलाए। छोकरा का वास्ते कोई अच्छा काम देखना मांगताए।'

बाबूराव- 'तो प्रॉब्लेम किदरकूं होताए? जो जीत के आएला उसकूं मिलने का।' अपुन बोला- 'बाबूराव, वो एकदम हलकट आदमी होताए। वो जास्ती पढ़ा-लिखा नईं। टपोरी का माफिक होताए। उसकूं अईसा प्रॉब्लेम समज में नईं आएंगा।' बाबूराव फुलटू फिलासफर बनके बोलताए- 'बॉस, अबी ये सोचने का नईं कि कऊन जीता अऊर कऊन गिरेलाए। वो जीतेला वोईच सिकंदर। अऊर सिकंदर का क्वालिटी कबी बी नईं देखने का।'

बाबूराव बोलताए, 'उसका पास बिंदास जाने का, प्रॉब्लेम बताने का। तुमारा बात कूं अईसा ध्यान से सुनेगा जईसा उसका भेजा का भीतर तुमारा अक्खा बात घुसेलाए। जबी तुम छोकरी का क्वालिफिकेशन बताएंगा कि वो एनवायरनमेंट साईंस का भीतर एमफिल किएला छोकरा का बताएंगा कि कोई कंपनी का भीतर इंटर्नशिप किएला, तबी तुम उसका थोबड़ा देखने का! मस्त मुंडी हिलाएंगा। उसका दिमाग का दही जम जाएंगा पन उसकूं ये बात समज में नईं आएंगा। भिड़, अपुन क्या बोलताए कि तुमारा काम होन दो कि मत होन दो, उसकूं बाजू में रखके खाली मजा लेने का।'

AI Image

अपुन की अबी सटकेली। अपुन कहेला- 'बाबूराव, अपुन उदर मजा लेने का वास्ते नईं जाएंगा। अपुन का काम होना मांगताए।' बाबूराव- 'बस, तुमारा साथ येईच प्रॉब्लेम होताए कि तुम जल्दी अंगार पकड़ लेताए। थोड़ा शांत होके अपुन कूं सुनने का। तुमकूं काम का बात बताएंगा। समज के लेने का! तुम जिदर बी जाएंगा न, अईसाईच क्वालिटी मिलताए। अबी जो इलेक्शन जीत के आएला, उसका क्वालिटी गौरमेंट बी नईं पूछताए। तुम कबी एरोप्लेन में चढ़ा क्या, नईं न? वो पैले दिन से लोकल ट्रेन का माफिक फ्लाइट से दिल्ली आएंगा-जाएंगा। उसका पंटर लोग बी दूसरा दिन से इनोवा, बोलेरो अऊर थार में बईठ के वड़ा-पाव खाने कूं जाएंगा। जो बी जीतताए वो लोकसभा, विधानसभा का भीतर बईठ के 'माननीय' बनताए। वो कोई बी आड़ा तिरछा सवाल पूछेगा तबी मिनिस्टर होन दो कि प्राइम मिनिस्टर, सीएम, सबकूं उसका जवाब देने कूं मांगताए। वो अईसा नईं बोलने कूं सकताए कि अपुन अईसा हलकट का जवाब नईं देगा। वो उसका क्वालिटी नईं पूछने कूं सकताए कि 'बाबा, बताओ तुमारा क्वालिटी चेक का स्टीकर किदर कूं लगेलाए? पैले अपुन तुमारा क्वालिटी देखेगा तबी जवाब देगा।' अईसा नईं होताए, भिड़!'

बाबूराव- 'अपुन एक बात अऊर बताताए। जो जिता भंगार होएंगा वो तुमारा उताईच मान देके काम करेगा। वो इस करके कि तुमारा काम का क्वालिटी बोले तो ओके होताए। नईं तो तुम जानताए न कि उसका पास भाई लोग कईसा-कईसा काम लेके जाताए? कोई सरकारी जमीन पे कब्जा करने का परमिशन मांगेगा तो कोई मर्डर केस में लॉकअप का भीतर किसी कूं छुड़ाने का वास्ते आएंगा। बिंदास जाके अपना काम कराने का! सिकंदर का क्वालिटी नईं देखने का। उसीच कूं बेस्ट क्वालिटी मानने का।'

शेयर करें अपने अनुभव
आम मुंबइया भाषा में यह लेख कैसा लगा हमें बताएं
nbtreader@timesgroup.com पर,
और सब्जेक्ट में लिखें-**'खाली पीली'**

खाली पीली

कौन जाएगा राज्यसभा?

लोकसभा चुनाव में विपक्षी खेमे के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन का साइड इफेक्ट अब राज्यसभा में देखने को मिलेगा। उन्हें लोकसभा में मिली जीत के बाद कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें सबसे अहम है बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से जीतने के बाद RJD नेता मीसा भारती की ओर से खाली की गई सीट। मीसा भारती राज्यसभा चुनाव में तब जीती थीं, जब RJD और JDU का गठबंधन था। तब वह आसानी से चुन ली गई थीं। लेकिन अब RJD का गठबंधन नहीं है और JDU, BJP के साथ है। ऐसे में RJD के लिए अब यह सीट जीतना मुमकिन नहीं। JDU इस सीट पर दावा कर रही है और BJP उसके कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकती है। अगर JDU को यह सीट मिलनी है तो फिर अगला सवाल होगा कि उसके यहां से कौन जाएगा राज्यसभा? JDU सूत्रों के अनुसार उससे पहले पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। इससे पार्टी के अंदर समीकरण बदलेगा। यह इस सीट की संभावित उम्मीदवारी का नाम भी प्रभावित कर सकता है। मीसा की खाली की गई सीट में अभी चार साल से अधिक का टर्म बाकी है।

AI Image

दक्षिण में दुविधा

मिशन दक्षिण के विस्तार में लगी BJP के लिए अन्नामलाई कुप्पुसामी एक अहम फैक्टर बन गए थे। तमिलनाडु में पार्टी ने उनसे बड़ी उम्मीदें पाल रखी थीं। लेकिन आम चुनाव में वोट मिलने के बावजूद पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। अब BJP वहां विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। वहां से आ रहे फीडबैक के अनुसार स्टालिन की अगुवाई वाली DMK सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी बहुत है। BJP इसे भुनाना चाहेगी। लेकिन पार्टी के अंदर बड़ा वर्ग अगले दो साल में होने वाले इस चुनाव के लिए AIADMK से गठबंधन करने के पक्ष में है, ऐसा शख्स, जो इतने से अर्थ पूरा नहीं होता। धमधूसर की अक्ल भी उसकी तरह होती है। बेवकूफी की बात पर वह बार-बार लड़ता रहता है। इसी अर्थ को पूरा करने के लिए अवध से लेकर मिथिला तक चौपट राजा वाली कहावत में धमधूसर राजा भी जोड़ते हैं। धमधूसर कोई आज का शब्द नहीं है। यह शब्द और नहीं तो कम से कम 400 साल पुराना है। तुलसीदास के जमाने के भी पहले का। कह सकते हैं कि चौपट शब्द के आने से पहले से ही धमधूसर सब कुछ चौपट करने पर उतारू था। कवितावली में तुलसीदास लिखते है, गुन ज्ञान-गुमान भभेरि बड़ी, कलपद्रुम काटत मूसर को। कलिकाल विचार अचार हरो, नहि सूझै कछू धमधूसर को। यानी ज्ञान के अहंकार में विचार इस तरह से नष्ट हो चुके हैं कि कलयुग में कौन बड़ा है या कौन छोटा, धमधूसर यानी बेवकूफ को कुछ नहीं दिखाई देता। जाहिर है, धमधूसरो से तुलसीदास भी काफी परेशान रहा करते थे। अंग्रेजी में इसका ऑप्शन flabby या फिर flaccid मिलता है। दिक्कत यह है कि इसमें धमधूसर की वह अक्ल और अहंकार नहीं दिखता, जो सदियों पहले तुलसीदास ने देख लिया था, और दर्ज भी कर दिया था।

बजट का दबाव

नई सरकार के लिए इस बार बजट में सबको खुश करने की बड़ी चुनौती है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू अपने प्रदेश के लिए बड़े पैकेज का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने समर्थन देने की एवज में अभी बस इसी मांग पर अपना फोकस बनाए रखा है। दरअसल राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर है कि उसे तुरंत मदद की दरकार है। लेकिन केंद्र सरकार की दुविधा है कि अगर एक राज्य को अलग से बड़ा पैकेज दिया तो दूसरे राज्यों का भी दबाव बढ़ जाएगा। बिहार पहले से इसकी मांग कर रहा है। ओडिशा भी ऐसी मांग करता रहा है, जहां अभी-अभी BJP की सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल से भी ऐसी मांग आ सकती है। ऐसे में बजट तैयार करते हुए इस मांग पर संतुलन बनाना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए खासा मुश्किल हो सकता है।

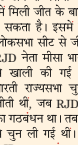

विशुद्ध राजनीति
पॉलिटॉक

सहयोगियों को संदेश

नरेंद्र मोदी की अगुवाई में NDA सरकार ने पिछले दिनों तीसरे टर्म के लिए शपथ ली। चौकाने वाली बात यह रही कि पहले ही दिन 71 मंत्रियों ने शपथ ले ली। पहले ही दिन इतना बड़ा मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी की शैली के विपरीत था। लेकिन इतने बड़े मंत्रिमंडल का गठन एक खास रणनीति के तहत किया गया। इस बार BJP बहुमत से दूर है और सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार की JDU और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP पर अधिक निर्भर रहेगी। ऐसे में इन दोनों सहित तमाम दूसरी पार्टियों को पहले दिन संदेश दे दिया गया कि मंत्रिमंडल में जो हिस्सेदारी मिली है, उसे आखिरी ही समझें। उन्हें अगले पांच साल इतने पर ही संतोष करना होगा। इससे अधिक कुछ मिलने की गुंजाइश नहीं बची है। माना जा रहा है कि 71 मंत्री बनने के बाद अब इसमें विस्तार नहीं होगा। अगर कुछ फेरबदल होता भी है तो वह जिम्मेदारी बदलने तक सीमित रहेगा। साफ है कि BJP ने इस मोर्चे पर पहले ही दिन स्पष्टता कर ली। पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा कि अगर छोटा मंत्रिमंडल पहले दिन शपथ लेता तो इसका विस्तार होने तक सहयोगी दल और हिस्सेदारी की अपेक्षा बनाए रखते और इसके लिए दबाव भी डाल सकते थे।

बड़बोले नेताओं पर काबू

आम चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी नेताओं को NDA से बेहतर जीत मिली। कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, पर इसका साइड इफेक्ट भी दिखा। कांग्रेस के नेता अपने सहयोगी नेताओं की हिस्सेदारी पर सवाल उठाने लगे। राज्य में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री और BJP नेता पीयूष गोयल की उद्धव ठाकरे से मुलाकात की भी खबरें आईं। इससे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के कान खड़े हुए। पार्टी ने तुरंत अपने बड़बोले नेताओं को मुंह बंद रखने की हिदायत दी। कहा गया कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बारे में सिर्फ राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खरगे बात करेंगे। साथ ही पार्टी नेताओं को संदेश दिया गया कि विधानसभा चुनाव भी एकजुट होकर लड़ना है। यह भी बता दिया गया कि यहां भी लोकसभा चुनाव की तरह कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। हालांकि चुनाव में महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करेगी या नहीं, अभी इस बारे में फैसला नहीं हुआ है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ पानी का सही इस्तेमाल

17 जून का संपादकीय 'जल का जंजाल' पढ़ा। एक तो भीषण गर्मी पड़ रही है, ऊपर से पानी की किल्लत है। समस्या दिल्ली की है, तो यहां की सरकार को हर हाल में पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। हरियाणा, हिमाचल की रट लगाने से लोगों की प्यास नहीं बुझ पाएगी। पानी की बर्बादी को रोकने पर सबसे पहले ध्यान देना होगा। आए दिन देखने को मिलता है कि सड़क के किनारे नलों से पानी बहता रहता है। जगह-जगह पाइपलाइन में लीकेज है। उसे तीक करना होगा। गार्डन में पानी की बर्बादी हो रही है। आरओ, एसी वगैरह से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल गार्डन, टॉयलेट में कर सकते हैं।

इन्द्र सिंह धिगान, किंग्जवे कैंप

■ आम लोगों की परेशानी

4 जून को 'खाली-पीली' कॉलम में 'करप्शन का 'क' बोलके बेजार नई होने का!' शीर्षक से प्रकाशित लेख **खाली पीली** पढ़ा। लेखक ने लोकसभा चुनाव के दिनों की बातों पर ध्यान दिलाया है। न आइडियॉलजी पर वोटर वोट देते हैं, न करप्शन पर ज्यादा मगजमारी करते हैं। आम वोटर तो महंगाई, रोजी-रोटी, सुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जीते कोई, हारे कोई आम जनता अपनी परेशानी में उलझी है। चुनाव के दिनों में नेता दरवाजे तक आ जाते हैं, पर जीतने के बाद शहर क्या अपने क्षेत्र को भी भूल जाते हैं।

रोहित सक्सेना, ईमेल से

■ युद्ध और न खिंचे

यह पत्र 15 जून के लेख 'मोदी बन सकते हैं शांति दूत' से संबंधित है। नई सरकार के शपथ लेते ही मोदी G7 में भाग लेने के लिए इटली गए हैं। फोकस रूस-यूक्रेन और हमास-इस्राइल युद्ध पर भी है। युद्ध बहुत लंबा खिंच गया है। इसे अब रुकना चाहिए। युद्ध करने वाले देशों के साथ-साथ पूरे विश्व में खाद्य संकट और कई तरह की परेशानियां पैदा हो गई हैं। लाखों लोगों को शरणार्थी बनकर जीना पड़ रहा है।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

ऑस्ट्रेलिया की जीत से खुश हुआ इंग्लैंड – एक खबर
– इंग्लैंड ये भी तो बताए कि उसका नंबर कब आएगा!

अनुपम सिंह

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

एक न एक दिन सबको जाना है फिर घमंड कैसा

आर.डी. अग्रवाल 'प्रेमी'

तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, 'जा के विधि दारुन दुख देहिं, वाकी मति पहिलेहिं हर लेहिं।' यानी जब किसी के जीवन में कष्ट आने वाला होता है, तब उसकी बुद्धि और विवेक दोनों चले जाते हैं। अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगता है। अहंकारी को सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनना ही सुहाता है। अपनी निंदा या आलोचना पर उसे क्रोध आता है। क्रोध से वह अपनों को भी पराया कर देता है। तब सच बात उस तक नहीं पहुंच पाती और यही उसके नाश का कारण बनता है।

कई प्रकार के नशे हैं, जिन्हें मनुष्य अनेक माध्यमों से ग्रहण करता है। परंतु एक नशा है, जिसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती और यह चुपके से मनुष्य में चढ़ जाता है। यह नशा है अहंकार का। कहा भी गया है कि माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है? अहंकार किसको नहीं हुआ है? बड़े-बड़े राजाओं को हुआ, ऋषियों-मुनियों को हुआ। साधारण इंसान को तो छोटी-सी बात का भी अहंकार झट से हो जाता है। नशे की चीजों से किया गया नशा तो कुछ घंटों के बाद उतर जाता है, लेकिन अहंकार का नशा जल्दी नहीं उतरता। वह जिंदगी भर ऐसा चढ़ा रहता है कि जब तक उतरता है, तब तक बहुत देर हो गई होती है और पछताता ही शेष रहता है। हिरण्यकश्यप और रावण जैसे शक्तिशाली दानवों को भी अहंकार हुआ और इसकी परिणति अंतकाल में हुई। महाभारत के संग्राम का कारण भी अहंकार था। आज बड़े-बड़े देश छोटे-छोटे देश महीनों से युद्ध कर रहे हैं और तनावग्रस्त हैं- सिर्फ अपने झूठे अहंकार के कारण। माया की चकाचौंध में मनुष्य भूल जाता है कि मैं क्या हूं? कौन हूं? अहंकार के नशे में चूर होकर अंधकार में भटक जाता है।

हवा के झोंके से उड़ता हुआ कोई सूखा पत्ता यह गर्व करता है कि मैं उड़ रहा हूं। लेकिन ज्यों ही वह जमीन पर गिरता है तो उसे महसूस होता है कि मैं तो हवा के कारण उड़ रहा था। अब मैं अपने तने से भी अलग हो गया और आसमान से भी नीचे गिरा। यही हाल मनुष्य का भी होता है जो अहंकार में सब कुछ भूल जाता है। कैसे टूटेगा अहंकार का यह नशा? क्या जीते जी इस अहंकार से मुक्ति मिल पाएगी। अहंकार के इस नशे से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले खुद ही को यह निर्णय लेना होगा कि मैं अहंकार से बचूं। संत-महात्मा कहते हैं कि जीवन में ज्ञान का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, उसी से अज्ञानता के अंधकार का नाश होगा।

अहंकार रूपी चोर हमारे अंदर प्रवेश कर आनंद को चुरा रहा है। उजाला होने पर जैसे चोर भाग जाते हैं, वैसे ही स्वयं का ज्ञान होते ही अहंकार रूपी चोर का पलायन हो जाएगा। इस ज्ञान का उजाला जितना बढ़ता जाएगा, अहंकार का भाव उसी अनुपात में घटता जाएगा। तभी हमें शांत और तनावहीन जीवन उपलब्ध हो सकेगा। किसी को भी इस पृथ्वी पर हमेशा नहीं रहना है, मनुष्य को सदैव इसका आभास रहना चाहिए। इसी से वैराग्य की भावना होगी कि भाई एक न एक दिन तो इस दुनिया से कूच कर जाना है। ज्ञान से, भक्ति से या वैराग्य से जिन्होंने भी अहंकार के इस नशे को समाप्त कर दिया, उन्होंने ही सहज जीवन बिताया।

आर.एन.आई. नं. 210012/56 प्रकाशित पुलिंदा। निर्दिष्ट अनुसार के बिना संपादन व आंशिक पुनर्संपादन पूर्वक: जीवनजित। नवभारतटाइम्स बिल्डिंग, कोटला मुबारक रोड, प्रकाशन विशेषांक के लिए राजेश पराशर द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई द